दिनांक-28.07.2014 को सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के प्रगति की समीक्षा हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

1. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।
2. श्री संजीव कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
3. श्री अनिल कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री जी.के.शतनारायणा ए.जी.एम. एण्ड स्टेट कॉर्डिनेटर ECIL
5. श्री जी. हेमचन्द्र राव, एस..डी.जी.एम., ECIL
6. श्री सत्य रंजन सीट, डी.जी.एम.,ECIL
7. श्री रंजन कुमार सिंह, पी.एस.ए., NIC, पटना ।
8. श्री नरेन्द्र कुमार, एस.एस.ए., NIC, पटना ।
9. श्री मुकेश कुमार Consultant ECIL पटना ।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के 133 पंचायतों के 279 EBs के Image की उपलब्धता के बिन्दु पर ECIL के प्रतिनिधि श्री हेमचन्द्र राव से पृच्छा की गई, इस संबंध में श्री राव के द्वारा सूचित किया कि 88 पंचायतों का Image उपलब्ध करा दिया गया है, शेष 45 पंचायतों का Image डाटा जिला प्रशासन को दे दिया गया है, उसकी जॉच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है । दिनांक-21.07.2014 को आहूत बैठक में ECIL प्रतिनिधि के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के Missing Images उपलब्ध कराने के संबंध में दिये गये आश्वासन पूरा नहीं होने पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खेद व्यक्त किया गया । राज्य समन्वयक, ECIL द्वारा इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराने का आश्वासन दिया गया ।

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, के द्वारा राज्य समन्वयक, ECIL को सुझाव दिया गया कि 8 हजार से अधिक प्रगणन खंड वाले जिलों (पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया एवं पूर्वी चम्पारण) का F- file NIC पर प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाये । वैसे जिले (दरभंगा, मधेपुरा, नालन्दा, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, जहानाबाद, सुपौल, बक्सर एवं अररिया) जहॉ Provisional F- file जेनरेशन एवं अपलोडिंग का कार्य 65 प्रतिशत से अधिक हो चुका है उन जिलों का F- file अगले सोमवार तक NIC पर अपलोड कराया जाये जिससे कि उन जिलों का NFSA के तहत Considered डाटा NIC दिल्ली से प्राप्त कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराया जा सके ।

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, द्वारा ECIL को यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य में F- file जेनरेशन एवं अपलोडिंग में नीचे से वैसे जिले (भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, पूर्वी चम्पारण एवं गया) जहॉ F- file अपलोडिंग का प्रतिशत 20 प्रतिशत या उससे कम हो वहॉ ECIL के प्रतिनिधि मिशन मोड में कार्य कर उक्त जिलों का F-file जेनरेशन एवं अपलोडिंग का कार्य अगले सोमवार तक निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करें ।

कार्य० 30.7.14

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ECIL के राज्य समन्वयक से पृच्छा की गई कि COTS के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों में से निष्पादन एवं अपलोडिंग हेतु शेष बचे हुये लगभग 18 लाख दावे/आपत्तियों को कब तक COTS सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किया जायेगा एवं उसका F-file जेनरेट कर NIC सर्वर पर अपलोड किया जाएगा? माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ECIL को सुझाव दिया गया कि पूर्व के लंबित दावे/आपत्तियों के अतिरिक्त नई व्यवस्था के तहत प्रखंडों में 15 जुलाई तक प्राप्त दावे/आपत्तियों को दिनांक-18.07.2014 तक निष्पादित करते हुए NIC सर्वर पर अपलोड किया जाये। इस प्रस्ताव पर बैठक में उपस्थित ECIL के प्रतिनिधियों द्वारा भी सहमति प्रदान की गई।

ECIL के राज्य समन्वयक, एवं श्री हेमचन्द्र राव द्वारा बतलाया गया कि 18 अगस्त तक सभी जिलों का F-file अपलोड कर दिया जायेगा तथा बैठक में विमर्शित बिन्दु पर सहमति पत्र दूसरे दिन विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(एस.एम.राजू)
सचिव 31/7/14

ज्ञापांक:- 19534 पटना, दिनांक :- 01-08-2014

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(वी.सी.)-103-12/2012

प्रतिलिपि :- श्री जी.के.शतनारायणा ए.जी.एम.एण्ड स्टेट कॉडिनेटर ECIL/श्री जी. हेमचन्द्र राव, एस..डी.जी.एम., ECIL/ श्री सत्य रंजन सीट, डी.जी.एम.,ECIL/ श्री रंजन कुमार सिंह, पी.एस.ए., NIC, पटना / श्री नरेन्द्र कुमार, एस.एस.ए., NIC, पटना / श्री मुकेश कुमार Consultant ECIL,पटना बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 31/7/14

ज्ञापांक:- 19534 पटना, दिनांक :- 01-08-2014

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(वी.सी.)-103-12/2012

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग/ माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 31/7/14

ज्ञापांक:- 19534 पटना, दिनांक :- 01-08-2014

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(वी.सी.)-103-12/2012

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 31/7/14

कार्य॰ 30.7.14